1	2	3	4
3.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचों को मजबूत बनाना	596.51	622.31
4.	कार्यात्मक साक्षरता जन कार्यक्रम . .	300.00	669.00
5.	स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता योजना . .	1948.00	1353.63
6.	श्रमिक विद्यापीठों . . .	92.15	97.59
7.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन . . .	344.10	185.00
8.	नेहरू युवक केन्द्रों	283.00	200.00
9.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण . .	13.59	8.36
10.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय . . .	214.96	285.90
11.	विशेष परियोजनाएं . . .	—	5978.90
12.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान . . .	—	8.50
	कुल : .	8841.00	13114.65

वनरोपण कार्यक्रम के विस्तार की योजनाएं

290. **श्री शंकर दयाल सिंह** : : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वनरोपण" कार्यक्रम का विस्तार करने तथा नये किस्म के पौधे लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयनार्थ गैर-सरकारी क्षेत्रों से भी मदद ले रही है या लेने जा रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वनरोपण के प्रयोजनार्थ अब तक किन-किन किस्मों के पौधे लगाए जाते रहे हैं तथा उनका पर्यावरण से क्या संबंध है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कमलनाथ) : (क) केन्द्र और राज्य प्लान स्कीमों के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं । सातवीं योजना अवधि (1985–90) के दौरान कुल 8.8 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए जबकि लक्ष्य 8.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का रखा गया था । वर्ष 1950 से 1985 तक की पिछली योजना अवधियों में कुल 8.2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर उक्त कार्यकलाप चलाए गए। आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम का विस्तार किए जाने की आशा है जो कि धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह व्यवस्था है कि व्यक्तियों और संस्थानों को उनकी अपनी भूमि पर वृक्ष-खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें सुविधायें प्रदान की जाएं, और यह भी कि जहां तक संभव हो वनों पर आधारित उद्योग अपेक्षित कच्चे माल को पैदा करें । इसके लिए विशेषकर उन व्यक्तियों के साथ जो कच्चा माल पैदा कर सकते हों के साथ सीधे संबंध स्थापित किया जाए और उन्हें ऋण, तकनीकी सलाह, कटाई और परिवहन सुविधायें आदि सहायता के रूप में दी जायें ।

नीति के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित विषयों के सन्दर्भ में कार्रवाई शुरू की गई है :—

(i) घरेलू और औद्योगिक तथा शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से लोगों की निजी भूमि पर फार्म वानिकी/ वि वानिकी को बढ़ावा देना ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार दिलाने तथा लोगों द्वारा स्थानीय तौर पर वांछित उत्तम किस्म की पौध प्रजातियां उपलब्ध कराने के लिए विकेन्द्रित जन-पौधशालाओं की स्थापना करना ।

(iii) निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों को काटने तथा उनके परिवहन पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा करने तथा उन्हें शिथिल बनाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना ।

(iv) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उडीसा तथा कर्नाटक राज्यों में वृक्ष उगाने वालों की सहकारितायें तथा फार्म वानिकी सहकारितायें स्थापित करना ।

(v) निजी भूमि पर वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने के लिए संस्थागत ऋण सुलभ करना ।

(vi) वनीकरण और परती भूमि विकास के राष्ट्रीय प्रयास में जन-सहभागिता प्राप्त करने हेतु कार्यतंत्र तैयार किए जाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कोष (जिसमें दिए अंशदान में कर राहत की सुविधा मिलती है) की स्थापना करना ।

(vii) जिन अवक्रमित वन भूमि की सुरक्षा तथा विकास के लिए ग्रामीण समुदाय सहमत हों उनसे प्राप्त उपज में उन्हें हिस्सेदार बनाना ।

(viii) निजी और सार्वजनिक भूमि पर वनीकरण और परती भूमि विकास कार्य कलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियो को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(ग) लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पर्यावरण में सुधार लाने की दृष्टि से मुख्यतः ईंधन लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी, फल तथा लघु वनोपज प्रदान करने वाली प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है ।

देश में मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या

291. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं ;

(ख) क्या मुक्त विश्वविद्यालयों और सामान्य विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों के बीच कोई अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो यह अंतर क्या है ; और

(घ) इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली की अब तक क्या उपलब्धि रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय 5 मुक्त विश्वविद्यालय हैं, अर्थात् :

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।

(2) आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।

(3) कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा ।

(4) यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक ।

(5) नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना ।

(ख) और (ग) मुक्त विश्वविद्यालयों तथा सामान्य/रूढ़िगत विश्वविद्यालयों में मुख्य अंतर, जो उनके कार्यकलापों में प्रतिबिम्बित हैं, निम्नलिखित हैं :—

(i) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रवेश के लिए पिछली शैक्षिक योग्यताओं